भारत संघ

बनाम

सावजीराम और अन्य

17 दिसंबर, 2003

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे.जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894: धारा 4,6,18,54- भूमि अधिग्रहण- मुआवजे की गणना- सामग्री के वर्तमान मूल्य और वर्तमान दरों पर निर्माण की लागत पर मुआवजे की गणना के लिए राज्य नियमावली प्रदान करता है - राज्य मूल्यह्रास के लिए कटौती का दावा करता है - माना जाता है, वर्तमान मूल्य और दरों की गणना करते समय मूल्यह्रास के प्रति कोई कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं है - कटौती के लिए राज्य नियमावली प्रदान करता है भूमि स्वामियों को सौंपी गई भूमि पर सामग्री का मूल्य कम करना - सामग्री हटाने के संबंध में परस्पर विरोधी दावे - पकड़े गए, सामग्री हटाने के दावों पर निर्णय लेने के लिए मामले को संदर्भ न्यायालय में भेज दिया गया, जिसमें पार्टियों को सामग्री और साक्ष्य अभिलेख पर रखने की अनुमति दी गई --मध्य प्रदेश की भूमि अधिग्रहण नियमावली-पेरा 43 और 44

शब्द और वाक्यांश-'मूल्यह्रास'-सामान्य बोलचाल में इसका अर्थ।

मध्य प्रदेश राज्य ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण कियाः

अपीलार्थी-भारत संघ जिस पर प्रत्यर्थियों-भूमि मालिकों ने घरों या संरचनाओं का निर्माण किया था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एल. ए. ओ.) ने घर के कुल मूल्यांकन से मूल्यह्रास के लिए 5 प्रतिशत की कटौती करने के बाद मुआवजे का निर्धारण किया। सिविल न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18 के तहत निर्देश देते हुए कहा कि भूमि मालिक 5 प्रतिशत मूल्यह्रास की कटौती के बिना घर के पूर्ण मूल्यांकन के हकदार हैं। भारत संघ ने एल. ए. ओ. के निर्णय के खिलाफ अधिनियम की धारा 54 के तहत अपील दायर की जो उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए, भारत संघ द्वारा यह अपील की गई।

अपीलार्थी ने मध्य प्रदेश की भूमि अधिग्रहण नियमावली के पैराग्राफ 43 और 44 के संदर्भ में तर्क दिया कि संदर्भ न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह मूल्यह्रास की अनुमति नहीं देता है और भूमि मालिकों को दी गई वस्तुओं के मूल्य में कटौती की भी अनुमति नहीं देता है।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि किसी भी मूल्यह्रास की कोई गुंजाइश नहीं है जब वर्तमान बाजार मूल्य नियमावली के पैरा 44 के संदर्भ में

निर्धारित किया जाना है और बड़ी संख्या में भूमि मालिकों ने भूमि पर खड़ी वस्तुएँ किसी भी मूल्य को नहीं हटाया है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 . आम तौर पर, आम तौर पर कहा जाए तो मूल्यह्रास एक निर्धारिती द्वारा अपने व्यवसाय में नियोजित पूंजीगत संपत्ति के टूट-फूट के कारण मूल्य में कमी के लिए एक भत्ता है। इसे अलग ढंग से कहें तो, मूल्यह्रास किसी परिसंपत्ति के उपयोग या उपयोग के कारण उसके प्रभावी जीवन का माप है दी गई अवधि के दौरान अप्रचलन. [1012-सी; 101 ए]

मैसूर मिनरल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, कर्नाटक,बैंगलोर, [1999] 7 एस. सी. सी. 106, संदर्भित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण); पार्क इन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस मूल्यांकन (5 वीं संस्करण, पृष्ठ 323); पैटन के खाते की पुस्तिका (तीसरा संस्करण,) और वेबस्टर्स न्यू वर्ड डिक्शनरी का उल्लेख किया गया है।

1.2. मध्य प्रदेश के भूमि अधिग्रहण नियमावली के पैरा 44 को पढ़ने से पता चलता है कि यह मुआवजे की गणना से संबंधित गणना की एक विधि है। घरों और इमारतों के मुआवजे की गणना (ए) सामग्री के वर्तमान मूल्य (बी) वर्तमान दरों पर निर्माण की लागत के अतिरिक्त की जानी चाहिए। मुआवज़ा निकालने के दोनों घटक वर्तमान मूल्य से संबंधित

हैंवर्तमान में निर्माण की सामग्री और लागत मालिक को सौंपी गई किसी भी सामग्री के मूल्य से कम है। जाहिर है, गणना वर्तमान मूल्य या वर्तमान दरों के आधार पर की जानी है मामला, हो सकता है. 'वर्तमान' शब्द का अर्थ उस समय अस्तित्व में होना, जिस समय कोई बात कही या लिखी जाती है, किसी निर्दिष्ट स्थान, वस्तु पर होना। जाहिर है इसलिए निर्माण की लागत पर पहुंचने के बाद मुआवज़ा तय करते समय या सामग्री का मूल्य निकालते समय प्रचलित दर में कोई और कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, मूल्यह्रास के संबंध में अपीलकर्ता-भारत संघ के रुख में कोई सार नहीं है। (1011-एफ-एच; 1012-ए, बी]

2.1 पैराग्राफ 43 और 44 का संयुक्त पठन निम्नलिखित स्थिति को स्पष्ट करता है। सबसे पहले, सरकार को यह निर्णय लेना होगा कि क्या जमीन पर खड़े घर, इमारतें और पेड़ सरकार द्वारा आवश्यक हैं। यदि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मालिक को एक उचित अवधि के भीतर घर, इमारत या पेड़ों को हटाने का विकल्प दिया जाता है। अवधि कलेक्टर द्वारा तय की जानी है और हटाई गई सामग्री का मूल्य पुरस्कार में निर्धारित किया जाना है। निर्धारित राशि को मुआवजे के रूप में देय राशि में से काटना होगा, यदि इसका भुगतान नहीं किया गया है और यदि इसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो सामग्री को हटाने से पहले मालिक से राशि की वसूली की जाएगी। मालिक को सौंपी गई सामग्री का मूल्य मुआवजे से काटा जाना चाहिए। [1013 - ई-जी]

2.2 भारत संघ के अनुसार, मालिकों को विकल्प दिया गया था और उन्होंने वास्तव में सामग्री को हटा दिया था। दावेदारों द्वारा इस दावे का खंडन किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संदर्भ न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने उन दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया है जिन पर संघ द्वारा निर्भरता रखी गई है और दावों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विस्तार से विचार किया है। इसलिए चीजों की योग्यता में, संदर्भ न्यायालय को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा दावा की गई सामग्री को हटाया गया था या दावेदार उत्तरदाताओं द्वारा दावा किए गए सामग्री को हटाया नहीं गया था। उचित अवसर देने के बाद संदर्भ न्यायालय द्वारा एक नया निर्णय लिया जाएगा। इस मामले को संदर्भ न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है ताकि बिना किसी देरी के, यथासंभव शीघ्रता से, सीमित प्रश्न पर निर्णय लिया जा सके। [1013 - एच; 1014-ए-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 9937/2003

1999 के एफ.ए.क्रमांक 247 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर के निर्णय और आदेश दिनांक 8.3.2000 से।

के साथ

सिविल अपील संख्यायें - 10062-64, 10061, 10025-60, 9938-10024, 10065-73 /2003

सुश्री सुषमा सूरी के लिए एन. एन. गोस्वामी, सुश्री इंदिरा साहनी और श्रीमती अनिल कटियार (एन. पी.) अपीलार्थियों के लिए।

ए. के. चिताले, एम. डी. आर्य, जय मंगलवाड़ी, नीरज शर्मा के लिए बी. एस. बंथिया और नवीन शर्मा उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति अरिजीत पासायत :

अनुमति दे दी गई।

इन अपीलों में, विचारणीय महत्व के दो दिलचस्प प्रश्न उठते हैं। वे मध्य प्रदेश राज्य में अर्जित भूमि के मूल्यांकन के लिए लागू मध्य प्रदेश के भूमि अधिग्रहण मैनुअल (संक्षेप में 'मैनुअल') के पैरा 43 और 44 से संबंधित हैं।

अनावश्यक विवरणों के बिना पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

भूमि अधिग्रहण की धारा 4 और 6 के तहत शक्तियों का प्रयोग- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 4 और 6 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य ने महू शहर में भारत संघ के लाभ के लिए कुछ भूमि का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहीत भूमि पर भूमि स्वामियों ने अपने मकान अथवा ढाँचे भी बना लिये थे। भूमि और उस पर बने मकानों/संरचनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिकारी (संक्षेप में 'एलएओ') के समक्ष मुआवजे के निर्धारण की कार्यवाही में, एक प्रश्न यह उठा कि मकानों/संरचनाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाए? एलएओ ने मूल्यह्रास की ओर 5% की कटौती के बाद घर का मुआवजा निर्धारित

किया। एलएओ के अनुसार, मकान भी मूल्यह्रास के अधीन हैं और तदनुसार उन्होंने मकान के कुल मूल्यांकन और जहां तक मकान से संबंधित मुआवजा निर्धारित किया गया था, से 5% की कटौती की। जहां तक यह घर से संबंधित है, मुआवजा निर्धारित किया गया था।

भूस्वामियों के कहने पर, अधिनियम की धारा 18 के तहत मामले को सिविल न्यायालय में भेजा गया था। सिविल कोर्ट के समक्ष, भूमि मालिकों का तर्क था कि एलएओ ने घर के मूल्य से मूल्यह्रास के रूप में 5% की कटौती करके गलती की है। उनके अनुसार, मूल्यह्रास के माध्यम से 5% की कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विद्वान संदर्भ न्यायाधीश ने भूमि मालिकों के उपरोक्त तर्क को स्वीकार कर लिया। उनकी राय में, घर के मूल्यांकन की गणना करते समय मूल्यह्रास की कटौती का कोई सवाल ही नहीं था। तदनुसार, घर के मूल्यह्रास के माध्यम से 5% की कटौती करने के निर्देश को खराब माना गया और यह निर्देश दिया गया कि भूमि मालिकों को मिलेगा एलएओ द्वारा निर्धारित 5% की कटौती के बिना घर का पूरा मूल्यांकन। विद्वान संदर्भ न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 13 में भूमि मालिकों के पक्ष में यही कहा:

"इसलिए उसे 5 प्रतिशत मूल्यह्रास के कारण राशि प्राप्त करने का अधिकार है जो पुरस्कार की राशि से काट ली गई है।"

एल. ए. ओ. के फैसले के खिलाफ, भारत संघ ने पहले अधिनियम की धारा 54 के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अनिवार्य

रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष दो मुद्दे उठाए गए थे। पहला प्रश्न मूल्यह्रास के अनुदान के संबंध में प्रश्न से संबंधित था। दूसरा अधिग्रहित भूमि के मूल स्वामी को दी गई सामग्री के मूल्य के लिए की जाने वाली कटौती, यदि कोई हो, के बारे में प्रश्न से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने पाया कि मूल्यह्रास के लिए किसी भी निर्धारण और सामग्री के मूल्य के लिए कोई कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तदनुसार, भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।

वर्तमान अपीलों में, उच्च न्यायालय के समक्ष दो बिंदुओं का आग्रह किया गया है, उन्हें नियमावली के पैराग्राफ 43 और 44 के संदर्भ में फिर से दोहराया गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि मूल्यांकन करते समय, भवन की आयु आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए और इसलिए, मूल्यह्रास प्रति बल प्रदान किया जाना चाहिए। जहाँ तक मालिकों को सौंपी गई सामग्री के मूल्य का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैरा 43 के संदर्भ में, मालिक को अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर खड़े किसी भी घर, भवन या पेड़ को हटाने का विकल्प दिया जाता है और पुरस्कार में निर्धारित ऐसी सामग्री के मूल्य को मुआवजे से काटना होता है। तत्काल मामले में भूमि मालिकों को विकल्प दिया गया था जिन्होंने सामग्री को हटा दिया था। इस संबंध में इंदौर के एल. ए. ओ., महू, जिला के एक पत्र का संदर्भ दिया जाता है। संक्षेप में, इसलिए, स्थिति यह है कि संदर्भ न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन अस्थिर है।

इसके विपरीत, दावेदारों -भूमि मालिकों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जब वर्तमान बाजार मूल्य को पैरा 44 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है तो किसी भी मूल्यह्रास की कोई गुंजाइश नहीं है। यह भूमि का मूल्यांकन और उस पर मौजूद बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन है जिसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अनुमत और कथित रूप से हटाई जाने वाली किसी भी संपत्ति के लिए मूल्यह्रास के आधार पर कोई कटौती करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह भी आग्रह किया गया कि बड़ी संख्या में दावेदारों ने कुछ भी नहीं हटाया और यह संदर्भ अदालत द्वारा तथ्यात्मक रूप से स्थिति पाई गई।

मूल्यह्रास के अनुदान और सामग्री की कटौती के संदर्भ में से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नियमावली के पैरा 43 और 44 को उद्धृत करने की आवश्यकता है। वे इस प्रकार पढ़ते हैं।

"43: यदि अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि पर खड़े किसी घर, भवन या पेड़ों की सरकार को आवश्यकता नहीं है, तो मालिक को कलेक्टर द्वारा तय की जाने वाली उचित अवधि के भीतर इसे हटाने का विकल्प दिया जा सकता है, जिस स्थिति में ऐसी सामग्रियों का मूल्य, जैसा कि पुरस्कार में निर्धारित किया गया है, मुआवजे के रूप में देय राशि से काट लिया जाएगा, या यदि मुआवजा दिया गया है सामग्री हटाने से पहले मालिक से पहले ही भुगतान कर लिया जाएगा।

44: घरों या इमारतों के लिए मुआवजे की गणना सामग्री के वर्तमान मूल्य और वर्तमान दरों पर निर्माण की लागत, मालिक को सौंपी गई किसी भी सामग्री के मूल्य को घटाकर की जानी चाहिए:

बशर्ते कि, यदि इमारतें अनुपयोगी हो गई हों, सामग्री के वर्तमान मूल्य पर ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिस जमीन पर इमारतें खड़ी हैं, उसका अलग से मुआवजा दिया जाए।

हालाँकि, जब इमारत और उसके स्थल मिलकर एक एकल संपत्ति बनती है, जिसका समग्र बाजार मूल्य होता है, तो निर्माण की लागत, सामग्री के मूल्य और स्थल के मूल्य के विवरण में जाना अनावश्यक है। संपूर्ण संपत्ति का बाजार मूल्य उसके मालिक को मिलने वाले किराए के संदर्भ में या समान इमारतों और उनकी स्थलों के निश्चित बिक्री मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है।

पैरा 44 को पढ़ने से पता चलता है कि यह मुआवजे की गणना से संबंधित गणना की एक विधि है। घरों और इमारतों के लिए मुआवजे की गणना (ए) सामग्री के वर्तमान मूल्य (बी) वर्तमान दरों पर निर्माण की लागत के अतिरिक्त की जानी चाहिए। मुआवजे की गणना के लिए दोनों घटक सामग्री के वर्तमान मूल्य और वर्तमान दरों पर निर्माण की लागत से संबंधित हैं मालिक को सौंपी गई किसी भी सामग्री का मूल्य कम होगा। जाहिर है, गणना वर्तमान मूल्य या वर्तमान दरों के आधार पर की जानी चाहिए, जैसा भी मामला हो। अभिव्यक्ति 'वर्तमान' का अर्थ है उस समय

अस्तित्वहीनता, जिस समय कुछ कहा या लिखा जाता है, एक निर्दिष्ट स्थान पर होना।

व्याकरणिक रूप से, इसका अर्थ है जब वर्णित क्रिया या घटना उच्चारण के समय हो रही हो या जब वक्ता कोई स्पष्ट लौकिक संदर्भ नहीं देना चाहता हो, तब उपयोग की जाने वाली क्रियाओं के काल को दर्शाना। इसका मतलब है कि समय अभी है। आम तौर पर, यह विचार के समय किसी विशेष वस्तु या मामले के अस्तित्व को दर्शाता है। जाहिर है इसलिए क्षतिपूर्ति तय करने या सामग्री के मूल्य का निर्धारण करने के समय प्रचलित दर पर निर्माण की लागत पर पहुंचने के बाद आगे कोई कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

आम तौर पर कहा जाए तो मूल्यह्रास एक निर्धारिती द्वारा अपने व्यवसाय में नियोजित पूंजीगत संपत्ति के टूट-फूट के कारण मूल्य में कमी के लिए एक भत्ता है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण) अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यह्रास को परिभाषित करता है:

"मूल्य में गिरावट; मूल्य में कमी। मूल्य में गिरावट, या हानि या कमी, उम्र, उपयोग और बेहतर तरीकों के कारण सुधार से उत्पन्न होती है। संपत्ति के मूल्य में गिरावट, टूट-फूट या अप्रचलन के कारण होती है और आमतौर पर इसके द्वारा मापी जाती है एक निर्धारित सूत्र जो संपत्ति के उपयोगी जीवन की एक निश्चित अवधि में इन तत्वों को दर्शाता है। कमाई के मुकाबले लागत का मिलान करने के लिए संपत्ति के अनुमानित उपयोगी

जीवन पर पूंजी निवेश की लागत का अनुमान लगाने और आवंटित करने की लगातार, क्रमिक प्रक्रिया।"

सिद्धांतों में पार्क $ प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूएशन (5 वां संस्करण, पृष्ठ 323 पर) में कहा गया है कि जहां तक भवन का सवाल है, मूल्यह्रास उपभोग, उपयोग, या समय के व्यय के माध्यम से घिसाव का माप है। पैटन ने अपने अकाउंट की हैंडबुक (तीसरा संस्करण) में देखा है कि मूल्यह्रास एक है किसी भी अन्य लागत की तरह अपनी जेब से खर्च करना। उन्होंने आगे देखा है कि मूल्यह्रास शुल्क केवल अचल संपत्ति लागत का आवधिक परिचालन पहलू है।

उपरोक्त स्थिति मैसूर मिनरल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयोग, कर्नाटक, बैंगलोर, [1999] 7 एस. सी. सी. 106 में नोट की गई थी।

वेबस्टर्स न्यू वर्ड डिक्शनरी के अनुसार, "मूल्यह्रास" का अर्थ है "घिसाव, गिरावट या अप्रचलन के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी; बही-खाता, लेखांकन में इसके लिए किया गया भत्ता आदि।"

दूसरे शब्दों में कहें तो, मूल्यह्रास किसी निश्चित अवधि के दौरान उपयोग या अप्रचलन के कारण किसी परिसंपत्ति के प्रभावी जीवन का माप है। इसलिए, मूल्यह्रास के संबंध में अपीलकर्ता-संघ के रुख में कोई दम नहीं है। अन्य प्रासंगिक प्रश्न जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है वह है - नियमावली के पैरा 43 और 44 में जो कुछ दिया गया है उसका सार। पैरा

43 के पढ़ने से पता चलता है कि जब कोई घर, इमारत या पेड़ों पर अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के लिए सरकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मालिक को कलेक्टर द्वारा तय की गई उचित अवधि के भीतर इसे हटाने का विकल्प दिया जाता है। विकल्प कलेक्टर द्वारा दिया जाना है और यह मालिक पर निर्भर है कि वह विकल्प का लाभ उठाए और कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय के भीतर सामग्री को हटा दे। एक बार वस्तुओं को हटाने के विकल्प का उपयोग करने के बाद, ऐसी सामग्रियों का मूल्य मुआवजे के रूप में देय राशि से घटाया जाना चाहिए, यदि भुगतान पहले ही नहीं किया गया हो। यदि मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो सामान हटाने से पहले इसे मालिक से वसूला जाना चाहिए। पैरा 43 के तहत सबसे पहले सरकार को यह तय करना होता है कि जमीन पर खड़े घर, इमारत या पेड़ों की सरकार को जरूरत है या नहीं और अगर जरूरत नहीं है तो हटाने का विकल्प दिया गया है। जैसा कि पैरा 44 में दिया गया है, उक्त पैरा में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर निकाले गए मुआवजे से मालिक को दी गई सामग्री का मूल्य घटाया जाना है। पैरा 43 और 44 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले सरकार को यह फैसला लेना होगा कि जमीन पर खड़े घर, इमारतें और पेड़ सरकार को चाहिए या नहीं। यदि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मालिक को उचित अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, घर, भवन या पेड़ों को हटाने का विकल्प दिया जाता है। अवधि कलेक्टर द्वारा तय की जानी है और हटाई गई सामग्री का मूल्य पुरस्कार में निर्धारित किया जाना है। निर्धारित

राशि को मुआवजे के रूप में देय राशि से काटा जाना चाहिए, यदि इसका भुगतान नहीं किया गया है और यदि इसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो सामग्री को हटाने से पहले मालिक से राशि की वसूली की जाएगी। मालिक को सौंपी गई सामग्री का मूल्य मुआवजे से काटा जाना चाहिए। संघ के अनुसार, मालिकों को विकल्प दिया गया था और उन्होंने वास्तव में सामग्री हटा दी थी। यह दावा दावेदारों के विद्वान वकील द्वारा विवादित है। उनके अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को देखते हुए जिनकी भूमि की आवश्यकता थी, नियमावली के पैरा 43 और 44 में अनुध्यात वस्तुओं और कटौती को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। किसी भी स्थिति में, जब अधिग्रहण बुनियादी ढांचे के साथ भूमि का होता है, तो आगे कटौती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है।

क्या हटाने का विकल्प भूमि के मालिक को दिया गया था यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय तथ्यात्मक रूप से किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी एक पत्र को रिकॉर्ड में रखा है जिसमें दिखाया गया है कि हटाने का ऐसा विकल्प दिया गया था। हलफनामे में आगे कहा गया है कि सामग्री वास्तव में हटा दी गई थी। यह दावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दावेदारों के विद्वान वकील द्वारा गंभीर रूप से विवादित है। ऐसा प्रतीत होता है कि संदर्भ न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उन दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया है जिन पर संघ द्वारा निर्भरता रखी गई है और निष्पक्ष रूप से दावों पर विस्तार से विचार

किया है। इसलिए चीजों की योग्यता में, संदर्भ न्यायालय को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा दावा की गई सामग्री को हटाया गया था या दावेदारों-उत्तरदाताओं द्वारा दावा किए जाने के अनुसार कोई निष्कासन नहीं हुआ था। चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए यह उचित होगा कि संदर्भ न्यायालय अकेले इस प्रश्न का निर्णय करे। पक्षकारों को अपने-अपने पक्ष के समर्थन में सामग्री और/या साक्ष्य रखने की अनुमति देना केवल सामग्री को हटाने के बारे में है। उचित अवसर देने के बाद संदर्भ न्यायालय द्वारा एक नया निर्णय लिया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहां तक उस मुद्दे का संबंध है, हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है और मामले को संदर्भ न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है ताकि हमारे (उपरोक्त) द्वारा बताए गए सीमित प्रश्न पर बिना किसी देरी के यथासंभव निर्णय लिया जा सके। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

ए के टी

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।